



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ३३३]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर ३, १९८१/ग्राहिण ११, १९०३

No. 333] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 1981/ASVINA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अमंत्रालय

प्रधिकारी

नई दिल्ली, ३ अक्टूबर, १९८१

प्रधानमंत्री निपो ५४९(अ) — केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबन्ध भविष्यनिधि, १९५२ (१९५२ का १९) की धारा ७ की उपधारा (१) के साथ पठित धारा ५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, १९५२ का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अधीत् —

१ (१) इस स्कीम का संधिष्ठ नाम कर्मचारी भविष्य निधि (पंचम संशोधन) स्कीम, १९८१ है।

(२) यह राजान्न में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होनी।

२. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, १९५२ में—

(२) विद्यमान पैरा ६९ वा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् —

“६४वा निवासगृह/फ्लैट के क्रय के लिये या किसी निवासगृह के संशिरण के लिये जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिये किसी उपयुक्त स्थल का अर्जन भी है, निधि से अद्यित

(१) आयुक्त या जहा आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उमका अधीनस्थ कार्ड अधिकारी किसी सदस्य के आवेदन को ऐसे प्रक्रम में जो

विहित किया जाए और इस पैरा में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, सदस्य के नाम जमा में से—

(क) किसी निवासगृह/फ्लैट जिसके अन्तर्गत अन्यों के साथ किसी संयुक्त स्वामित्व के भवन में किसी फ्लैट के (पूरी रूप से या प्रवक्त्व पर क्रय के लिए या किसी निवासगृह के संशिरण के लिये जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सहकारी सोसाइटी, किसी संस्था, किसी न्यास, किसी स्थानीय निकाय या किसी गृह निमाण वित्तपोषण निगम (जिसे हममें इसके पावत अभिकरण कहा गया है) से उपयुक्त स्थल का अर्जन भी है, के लिए, या

(ख) किसी निवासगृह के संशिरण के प्रयोजन के लिये कोई निवास स्थल क्रय करने के लिए या किसी व्यष्टि से पहले से ही निमित निवासगृह/फ्लैट के किन्तु ऐसा गृह/फ्लैट जिसे क्रय किया जाना है जो तथा और जिसमें निवास न किया गया हो क्रय करने के लिये, या

(ग) किसी सदस्य या ऐसे सदस्य के पति या पत्नी या सदस्य और पति या पत्नी के संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन किसी निवास स्थल पर निवासगृह के संशिरण के लिए, या ऐसे निवास स्थल पर पहले से ही सदस्य या उसके पति या उसके पति या पत्नी द्वारा आरम्भ किए गए किसी निवासगृह के संशिरण को पूरा करने या जारी रखने के लिए, रकम अद्यित के रूप में मज़बूर कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इस पैरा में 'गहकारी सोसाइटी' पद में भवतारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी गज्य में सहकारी सोसाइटीयों से संबंधित नशामय प्रवृत्त विषय के अधीन रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन ममकी गई सोसाइटी अधिवेन है।

स्पष्टीकरण 2—इस पैरा में किसी नए और निवास न किए गए गृह के तथ्य का अधिकारण भवत के नक्शे के अनुमोदन के संबंधीक और जिसकी तारीख, गृह/फैट के संश्लिष्टि के प्रारम्भ और पूरा होने से संबंधित प्रमाणपत्रों और समुचित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कर विलों तथा ग्रसीदों के संबंध से और जहाँ कहाँ भी आवश्यक हों पड़ामियों से जाकर पड़ताल करके किया जाएगा।

(2) अधिम की रकम, सदस्य की बोकीम माम की मुक्त मञ्जूरी और मंहगाई भत्ते से या दैरा 69 के उपर्यैरा (3) के अधीन अनुज्ञेय नियोजक द्वारा अधिवाय किए जाने वाले अंश महित, स्थल सदस्य के अधिकाय का अंश यदि सदस्य के संबाय के प्राधिकरण की तारीख को अपना संचय उस पर व्याज सहित प्रत्याहरण करने के लिए अनुज्ञान किया होता या निवास स्थल के अर्जन या निवास गृह/फैट के ब्रय या निवासगृह के संश्लिष्टि के लिए वास्तविक लागत इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(3)(क) इस पैरा के अधीन कोई अधिम तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, अब तक कि—

- सदस्य ने निधि की सदस्यता के पांच बर्ष पूरे नहीं कर लिए हैं;
- निधि में सदस्य के नाम जमा रकम में अधिकारियों का उमका अपना अंश उस पर व्याज सहित एक हजार रुपये से कम नहीं है;
- निवास स्थल या निवासगृह/फैट या निर्माणाधीन गृह विलंगमियों से मुक्त नहीं है:

परन्तु जहाँ कोई निवास स्थल या निवासगृह फैट उप पैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अधिकरणों के पास केवल निवासगृह/फैट का क्रय करने या निवास गृह/फैट के संश्लिष्टि के लिये जिसके अस्त-गंत उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थल का अर्जन भी है धन प्राप्त करने के लिये बंधक रखा जाना है वहाँ, यथास्थिति, अब या अर्जन, रकम के प्रत्याहरण से छह मास के भीतर किया जाएगा:

परन्तु यह और कि किसी निवासगृह/फैट के संश्लिष्टि के लिये शाखत पट्टे पर या 30 बर्ष से अन्यून की अवधि के लिए पट्टे पर अर्जित भूमि या इस प्रकार पट्टुकृत भूमि पर बना कोई निवासगृह/फैट विलंगमिन सम्पत्ति नहीं समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी जहाँ निवासगृह/फैट का स्थल उपर्यैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अधिकरण के नाम में घारित है और ऐसे अधिकरण द्वारा उसके पूर्वानुभोवन के बिना ऐसे आवंटिती को निवासगृह/फैट का अन्तरण करने या अस्थाया व्ययन करने से प्रवारित किया जाना है वहाँ मात्र यह तथ्य कि अधिकरण के नाम में घारित गृह/फैट या स्थल पर आवंटिती का स्वामित्व का संपूर्ण अधिकार नहीं है, उसे उपर्यैरा (1) के खण्ड (क) के अधीन अधिम दिए जाने से यदि इस पैरा में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा कर दिया जाता है, वर्जित नहीं करेगा।

(4) संयुक्त स्वामित्व वाली किसी सम्पत्ति का क्रय करने या संयुक्त स्वामित्व वाले स्थल पर गृह संश्लिष्टि करने के लिए,

पति या पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व में स्थल को छोड़कर, कोई अधिम मंजूर नहीं किया जायगा।

(4) उपर्यैरा (2) में विहित निर्बन्धन के अधीन रहते हुए,

(क) जहाँ अधिम उपर्यैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अधिकरण से कोई निवासगृह/फैट या निवास स्थल के क्रय के लिए है वहाँ अधिम का संदाय सदस्य को नहीं किया जायगा अपितु एक या अधिक किस्तों में जैसे भी सदस्य द्वारा प्राधिकृत की जाए, सीधे अधिकरण को ही किया जायगा;

(ख) जहाँ अधिम किसी नियाम गृह के संश्लिष्टि के लिए है वहाँ वह इतनी किस्तों में मंजूर किया जायगा विविध अन्यून या जहाँ प्रायुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया जाए, उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी उचित समझता है;

(ग) जहाँ अधिम किसी व्यक्ति या अधिकरण से किसी निवास स्थल के प्रजेत के लिये है, वहाँ वह रकम ऐसी किस्तों में, जो बराबर की दो किस्तों से कम नहीं है पहली किस्त निवास स्थल का अर्जन करते समय और शेष ऐसे निवास स्थल पर निवासगृह का संश्लिष्टि करते समय, उसके अनुरूप पर संरक्षण की जाएगी।

(5) जहाँ कोई अधिम किसी निवासगृह के संश्लिष्टि के लिए मंजूर किया जाता है वहाँ संश्लिष्टि प्रत्याहरण की प्रथम किस्त से छह मास के भीतर प्रारंभ किया जायगा और प्रत्याहरण की अंतिम किस्त से बारह मास के भीतर उसे पूरा करना होगा। जहाँ कोई अधिम किसी निवासगृह/फैट के क्रय के लिये या निवासस्थल के अर्जन के लिये मंजूर किया जाता है वहाँ, यथास्थिति, अब या अर्जन, रकम के प्रत्याहरण से छह मास के भीतर किया जाएगा;

परन्तु यह उपबंध किसी निवासगृह/फैट के अवक्य पर क्रय की दशा में उन वशाओं में लागू नहीं होगा जहाँ निवास स्थल का अर्जन किया जाना है या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के नियमित गृहों का संश्लिष्टि सदस्यों को प्रावंटन करने की वृद्धि से करना।

(6) उपर्यैरा (7) में विर्तिविद्युत वशाओं को छोड़कर इस पैरा के अधीन आगे कोई अधिम नहीं किया जायगा।

(7) किसी सदस्य के या उसके पति या पत्नी के या सदस्य और पति या पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में किसी निवासगृह में परिवर्तनों बड़े दैराने पर परिवर्तनों या सुधारों के लिये सदस्य को छह मास तक की मूल मञ्जूरी और मंहगाई भत्ते या निधि में उसके अधिकारियों का अंश जमा रकम इनमें से जो भी कम हो, एक बार और केवल एक ही किस्त अतिरिक्त अधिम के रूप में मंजूर की जा सकेगी:

परन्तु यह कि अधिम, निवासगृह के पूरा होने की तारीख से पांच बर्ष की अवधि के पश्चात ही अनुज्ञय होगा।

(8) सदस्य हक-विलेख और ऐसी अन्य दस्तावेजों जो निरीक्षण के लिये अपवेक्षित हों ऐसे करेगा जिन्हे अधिम मंजूर किए जाने के पश्चात् वापस कर दिया जायगा।

(9)(क) यदि इस पैरा के अधीन मंजूर किया गया अधिम जिस प्रयोजन के लिये वह मंजूर किया गया था, वास्तविक अव्य की गई रकम से अधिक है तो अधिक का किसी निवासगृह का यथास्थिति अब पूरा होने पर या संश्लिष्टि पूरा होने पर या आवश्यक परिवर्तनों, परिवर्तनों या सुधारों के पूरा होने के तीस विन के भीतर सदस्य द्वारा निधि में प्रतिसंदाय एकमुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रतिसंदाय रकम निधि में सदस्य के आगे में नियोजक के अधिकारियों के अंश के रूप में उक्त अंश में मंजूर किए गए अधिम की सीमा तक, जमा की जाएगी और अधिमांश, यदि कोई हो सदस्य के खाते में उसके अधिकारियों के अंश में जमा किया जायगा।

(9) सदस्य को किसी निवासस्थल/निवास गृह/पैट भावधित न किए जाने की दशा में या सदस्य का प्रावंटन रद्द किए जाने और उप-पैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिकरण द्वारा रकम का प्रतिसंवाद कर दिए जाने की दशा में या सदस्य द्वारा किसी निवास स्थल का अर्जन करने या निवास गृह/पैट का किसी अधिकरण से क्य करने या निवासगृह का संश्लिष्ट करने में असमर्थ होने की दशा में सदस्य इस पैरा के अधीन यथास्थिति उसे अधिम की गई रकम का या उप-पैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिकरण को भेजी गई अधिम की रकम का निधि में एकमुक्त प्रतिसंदाय ऐसी रीति में करने का बायी होगा जो यथास्थिति प्रायुक्त या जहाँ प्रायुक्त द्वारा ऐसे प्राप्तिकृत किया जाए, उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी विनियोग करे।

इस प्रकार प्रतिसंवत्त रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अधिकारों के अंश के रूप में उस अंश में से मंजूर किए गए अधिम की सीमा तक जमा की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, सदस्य के खाते में उसके अधिकारों के अंश में जगा किया जायगा।

(10) यदि प्रायुक्त या जहाँ प्रायुक्त द्वारा ऐसे प्राप्तिकृत किया जाए उसका अधीनस्थ किसी अधिकारी का यह समापन हो जाता है कि इस पैरा के अधीन मंजूर किए गए अधिम का उस प्रयोजन से नियोग लिये वह मंजूर किया गया था अधिकरण के लिये उपयोग किया गया है या सदस्य ने आवंटन स्वीकार करने से या निवास गृह का अर्जन करने से हंकर कर दिया था या अधिम को शर्तें पूरी नहीं की गई हैं या ऐसी युक्तियुक्त प्राप्ति का है कि वे पूर्णतया/या भागतः पूरी नहीं की जाएँगी या कि उप-पैरा (9) के खण्ड (क) के नियोगों के अनुसार अधिक रकम का प्रतिवर्त्य नहीं किया जाएँगा। उप-पैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिकरण द्वारा सदस्य को बापस भेजी गई रकम का उप-पैरा (9) के खण्ड (क) के नियोगों के अनुसार प्रतिसंदाय नहीं किया जायगा तो प्रायुक्त या जहाँ प्रायुक्त द्वारा ऐसे प्राप्तिकृत किया जाए उसका अधीनस्थ अधिकारी सदस्य की मजदूरी से शोषण रकम और उन पर दो प्रतिशत प्रतिवर्त्य की दर पर शास्त्रिक ब्याज सहित शोषण रकम की, उतनी किस्तों में जो प्रायुक्त या जहाँ प्रायुक्त द्वारा ऐसे प्राप्तिकृत किया जाए उसका अधीनस्थ अधिकारी अवधारित करे, कटौती करने के लिये तुरन्त कवर उठाएगा। ऐसी बमूली के प्रयोजन के लिये आपुकृत या जहाँ प्रायुक्त द्वारा ऐसे प्राप्तिकृत उसका अधीनस्थ अधिकारी नियोजक को सदस्य की मजदूरी से ऐसी किस्त की कटौती करने के लिये निवेश वे सकेगा और ऐसे निवेश प्राप्त होने पर नियोजक तदनुसार कटौती करेगा। इस प्रकार कटौती की गई रकम नियोजक द्वारा प्रायुक्त को या जहाँ प्रायुक्त द्वारा ऐसे प्राप्तिकृत किया जाए उसके अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे समय के सीनार और ऐसी रीति में प्रेषित की जाएगी जो निवेश में विनियोग की जाए। शास्त्रिक ब्याज को छोड़कर इस प्रकार प्रतिसंवत्त रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अधिकारों के अंश में उक्त अंश में से मंजूर किए गए अधिम की सीमा तक, जमा की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, सदस्य के खाते में उसके अधिकारों के अंश में जमा की जाएगी। प्राप्तिकृत का ब्याज की रकम शास्त्रिक ब्याज उचित खाते में जमा की जाएगी।

(11) जहाँ इस पैरा के अधीन मंजूर किए गए अधिम का सदस्य द्वारा तुरन्त योग किया गया है वहाँ इस पैरा के अधीन उक्त अधिम मंजूर करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या उक्त अधिम की रकम की उर पर शास्त्रिक ब्याज सहित पूरी बमूली की तारीख तक इनमें से जो भी पञ्चातवरी हो और अधिम मंजूर नहीं किया जायेगा।

(2) विद्यमान पैरा 68-ग हटा दिया जायगा।

(3) विद्यमान पैरा 68-घ के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायगा।
प्रथात् :—

“68घ. निधि में से अधिम का प्रतिसंवेद्य होना जैसा प्रत्यया उपबंधित है उसके सिवाय पैरा 68ब और 68बब के प्रधीन छिए गए अधिम प्रतिसंवेद्य होंगे।”

(4) विद्यमान पैरा 68घ के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा। प्रथात् :—

“68झ. सदस्यता की अवधि की संगता : किसी सदस्य की पैरा 68ब, 68बब और 68ट के अधीन सदस्यता की अवधि की संगतन करने में इस स्थिति के उसे लागू होने के पूर्व उसी नियोजक या कारबाने/स्थापन के अधीन व्यववाह की अवधि को छोड़कर उसको कुल सेवा और उसकी सदस्यता की अवधि जाते वह यथास्थिति निधि या लूट प्राप्त कारबाने/स्थापनों को प्राइवेट अविव्यनिधि या चालू सदस्यता के ठीक पूर्व की पैरा 27 या पैरा 27 के अधीन लूट प्राप्त कर्मचारी के रूप में अवधि है, सम्मिलित की जाएगी।

परन्तु यह कि सदस्य ऐसी अवधि के द्वारा अपनी अविव्य निधि क प्रत्याशूरण करके सदस्यता से पृथक नहीं हो गया है ;
(5) विद्यमान पैरा 68घ से 68छ हटा दिया जाएगा।

[सं० एस० 70012/(8)/81पी०फ०II]

नवीन आवला, उप मंत्रिक

MINISTRY OF LABOUR NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1981

G.S.R. 549(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,

(1) for the existing paragraph 68B, the following paragraph shall be substituted :—

“68B Advance from the Fund for the purchase of a dwelling house/flat or for the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose ;

(1) The Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may on an application from a member in such form as may be prescribed and subject to the conditions prescribed in this paragraph sanction from the amount standing to the credit of the member in the Fund, an advance—

(a) for purchasing a dwelling house/flat, including a flat in a building owned jointly with others (out-right or on hire purchase basis), or for constructing dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose from the Central Government, the State Government, a cooperative society, an institution, a trust, a local body or a Housing Finance Corporation (hereinafter referred to as the agency/agencies);

OR

(b) for purchasing a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house or a ready-built dwelling house/flat from any individual provided the said house/flat to be purchased is new and un-lived one ;

OR

- (c) for the construction of a dwelling house on a site owned by the member or the spouse of the member or jointly by the member and the spouse, or for completing/continuing the construction of a dwelling house already commenced by the member or the spouse, on such site.

Explanation 1: In this paragraph, the expression, 'cooperative society' means a society registered or deemed to be registered under the Cooperative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to co-operative societies.

Explanation 2 : In this paragraph, the fact of a new and unlied in house/flat shall be determined with reference to the certificates relating to the number and date of approval of the building plan, the date of commencement and completion of the house/flat, and the tax bills and receipts issued by the appropriate authorities, and wherever necessary, by neighbourhood enquired.

(2) The amount of advance shall not exceed the member's basic wages and dearness allowance for twenty four months or the member's own share of contributions, together with that amount of the employer's share of contributions admissible under sub-paragraph (3) of paragraph 69, had the member been allowed to withdraw his accumulations on the date of authorisation of payment with interest thereon or the actual cost towards the acquisition of the dwelling site or the purchase of the dwelling house/flat or the construction of the dwelling house, whichever is the least.

(3) (a) No advance under this paragraph shall be granted unless :

- (i) the member has completed five years' membership of the Fund ;
- (ii) the member's own share of contributions with interest thereon in the amount standing to his credit in the Fund is not less than one thousand rupees ;
- (iii) the dwelling site or the dwelling house/flat or the house under construction is free from encumbrances:

Provided that where a dwelling site or a dwelling house/flat is mortgaged to any of the agencies, referred to in clause (a) of sub-paragraph (1), solely for having obtained funds for the purchase of a dwelling house/flat or for the construction of a dwelling house including the requisition of a suitable site for the purpose, such a dwelling site or a dwelling house/flat as the case may be shall not be deemed to be an encumbered property :

Provided further that a land acquired on a perpetual lease or on lease for a period of not less than 30 years for constructing a dwelling house/flat, or a house/flat built on such a leased land, shall also not be deemed to be an encumbered property.

Provided also that where the site of the dwelling house/flat is held in the name of any agency, referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) and the allottee is precluded from transferring or otherwise disposing of, the house/flat, without the prior approval of such agency, the mere fact that the allottee does not have absolute right of ownership of the house/flat and the site is held in the name of the agency, shall not be a bar to the giving of an advance under clause (a) of sub-paragraph (1), if the other conditions mentioned in this paragraph are satisfied.

(b) No advance shall be granted for purchasing a share in a joint property or for constructing a house on a site owned jointly except on a site owned jointly with the spouse.

(4) Subject to the limitation prescribed in sub-paragraph (2)—

- (a) where the advance is for the purchase of a dwelling house/flat or a dwelling site from an agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1), the payment of advance shall not be made to the

member but shall be made direct to the agency in one or more instruments, as may be authorised by the member;

- (b) where the advance is for the construction of a dwelling house, it may be sanctioned in such number of instalments as the Commissioner or where so authorised by the Commissioner, any officer, subordinate to him, thinks fit.

- (c) where the advance is for the acquisition of a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house thereon from any individual or any agency, the amount shall be paid in not less than two equal instalments, the first instalment at the time of the acquisition of the dwelling site and the remaining at his request at the time of the construction of a dwelling house on such dwelling site.

(5) Where an advance is sanctioned for the construction of a dwelling house, the construction shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within twelve months of the withdrawal of the final instalments. Where the advance is sanctioned for the purchase of a dwelling house/flat or for the acquisition of a dwelling site, the purchase or acquisition, as the case may be, shall be completed within six months of the withdrawal of the amount :

Provided that this provision shall not be applicable in case of purchase of a dwelling house/flat or hire-purchase basis and in cases where a dwelling site is to be acquired or houses are to be constructed by a cooperative society on behalf of its members with a view to their allotment to the members.

(6) Except in the cases specified in sub-paragraph (7), no further advance shall be admissible to a member under this paragraph.

(7) An additional advance upto six months' basic wages and dearness allowance or the member's own share of contributions with interest thereon, in the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, may be granted once and in one instalment only, for additions, substantial alterations or improvements necessary to the dwelling house owned by the member or by the spouse or jointly by the member and the spouse :

Provided that the advance shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house.

(8) The member shall produce the title deed and such other documents as may be required for inspection which shall be returned to the member after the grant of advance.

(9) (a) If the advance granted under this paragraph exceeds the amount actually spent for the purpose for which it was sanctioned, the excess amount shall be refunded by the member to the Fund in one lump sum within thirty days of the finalisation of the purchase, or the completion of the construction of, or necessary additions, alterations or improvements to a dwelling house, as the case may be. The amount so refunded shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's share of contributions in his account.

(b) In the event of the member not having been allotted a dwelling site/dwelling house/flat, or in the event of the cancellation of an allotment made to the member and of the refund of the amount by the agency, referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) or in the event of the member not being able to acquire the dwelling site or to purchase the dwelling house/flat from any individual or to construct the dwelling house, the member shall be liable to refund to the Fund in one lump sum and in such manner as may be specified by the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, the amount of advance remitted under this paragraph to him or, as the case may be, to the agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1).

The amount so refunded shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund, to the extent of advance granted out of the said share, and the balance if any shall be credited to the member's own share of contributions in his account.

(10) If the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him is satisfied that the advance granted under this paragraph has been utilised for a purpose other than that for which it was granted or that the member refused to accept an allotment or to acquire a dwelling site or that the conditions of advances have not been fulfilled or that there is reasonable apprehension that they will not be fulfilled wholly or partly; or that the excess amount will not be refunded in terms of clause (a) of subparagraph (9) or that the amount remitted back to the member by any agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1), will not be refunded in terms of clause (b) of sub-paragraph (9), the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, shall forthwith take steps to recover the amount due with penal interest thereon at the rate of two per cent per annum from the wages of the member in such number of instalments as the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may determine. For the purpose of such recovery the Commissioner or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him may direct the employer to deduct such instalment from the wages of the member and on receipt of such direction, the employer shall deduct accordingly. The amount so deducted, shall be remitted by the employer to the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him within such time and in such manner as may be specified in the direction. The amount so refunded, excluding the penal interest, shall be credited to the employer's share of contributions in the member's amount in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance if any shall be credited to the member's own share of contributions in his account. The amount of penal interest shall however, be credited to the Interest Suspense Account.

(11) Where any advance granted under this paragraph has been misused by the member, no further advance shall be granted to him under this paragraph within a period of three years from the date of grant of the said advance or till the full recovery of the amount of the said advance, with penal interest thereon, whichever is latter."

(2) The existing paragraph 68-C shall be deleted;

(3) for the existing paragraph 68-D, the following paragraph shall be substituted :—

"68-D.—Advance from the Fund to be non-refundable : Except as otherwise provided the advances given under paragraph 68B and 68BB shall be non-refundable";

(4) for the existing paragraph 68-E, the following paragraph shall be substituted :—

"68-E.—Computation of period of membership : In computing the period of membership of the Fund of a member under paragraphs 68B, 68BB and 68K, his total service exclusive of periods of breaks under the same employer or factory/establishment before this scheme applied to him, as well as the periods of his membership, whether of the Fund or of private provident fund of exempted factories/establishments or as an employee exempted under paragraph 27 or 27A as the case may be, immediately preceding the current membership of the Fund, shall be included :

Provided that the member has not severed his membership by withdrawal of his provident fund during such period";

(5) The existing paragraphs 68F to 68GG shall be deleted.

[No. S 70012[8]81-PF. II]

N. B. CHAWLA, Dy. Secy

